Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal, Impact Factor: 6.1

ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 5; 2025; Page No. 90-94

Special Issue of International Seminar (23rd - 24th August, 2025)
On the Topic
Indian Knowledge System (IKS): Challenges & its Application in Higher Education for Sustainable Development
By
Faculty of Education, IASE (DU), Sardarshahar, Churu, Rajasthan - 331403

मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता में सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था की भूमिका का अध्ययन

[1]डॉ. आरती कोरी एवं [2]नेहा सिंह

[1]प्रोफेसर, गृह विज्ञान, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत
[2]शोधार्थी, गृह विज्ञान, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21427903

Corresponding Author: डॉ. आरती कोरी

सारांश

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि सामुदायिक सहभागिता तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता को किस प्रकार प्रभावित करती है। अध्ययन में उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के करनैलगंज एवं परसपुर विकास खण्डों के चयनित 10 ग्रामों की 400 ग्रामीण महिलाओं को उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण के आधार पर शामिल किया गया तथा सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि जिन क्षेत्रों में समुदाय की सहभागिता अधिक तथा निगरानी व्यवस्था प्रभावी थी, वहाँ मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता का स्तर उल्लेखनीय रूप से अधिक पाया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण में $\chi^2 = 74.58$, $df = 2$ तथा p-value = 0.000 प्राप्त होने के कारण यह सिद्ध हुआ कि सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था का कार्यक्रमों की सफलता पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हुई। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, स्वयं सहायता समूहों तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं की पहुँच, पारदर्शिता, जवाबदेही, सेवा-गुणवत्ता एवं लाभार्थियों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। साथ ही नियमित सामाजिक अंकेक्षण, सामुदायिक निगरानी तथा स्थानीय उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन तथा समुदाय आधारित संगठनों के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करता है तथा मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी, सहभागी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: मातृत्व एवं बाल विकास, सामुदायिक सहभागिता, निगरानी व्यवस्था, आईसीडीएस, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, महिला एवं बाल कल्याण इत्यादि।

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिनमें समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), जननी सुरक्षा योजना (JSY), पोषण अभियान, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), टीकाकरण कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाएँ प्रमुख हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा छह वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, परामर्श एवं प्रारंभिक शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराना है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु-दर में कमी लाई जा सके तथा कुपोषण, एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रभावी निराकरण किया जा सकेायद्यपि सरकार द्वारा इन योजनाओं के संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन तथा प्रशासनिक तंत्र

उपलब्ध कराया गया है, तथापि अनेक क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसका प्रमुख कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि समुदाय की सीमित सहभागिता, लाभार्थियों में जागरूकता का अभाव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ, स्थानीय स्तर पर समन्वय की कमी तथा निगरानी व्यवस्था की कमजोरियाँ भी हैं। अनेक बार योजनाओं की जानकारी समय पर लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाती, सेवाओं की गुणवत्ता में असमानता दिखाई देती है, पात्र लाभार्थियों का पूर्ण पंजीकरण नहीं हो पाता तथा उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप योजनाओं के उद्देश्य एवं वास्तविक उपलब्धियों के मध्य अंतर बना रहता है।

वर्तमान समय में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि किसी भी सामाजिक विकास कार्यक्रम की सफलता केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, विद्यालय प्रबंधन समितियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा स्थानीय नेतृत्व की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है। सामुदायिक सहभागिता से योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है, लाभार्थियों का विश्वास मजबूत होता है, सेवाओं की पहुँच एवं उपयोगिता में वृद्धि होती है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है। जब समुदाय स्वयं योजना निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रक्रिया में भाग लेता है, तब कार्यक्रम अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा टिकाऊ बनते हैं।

इसी प्रकार, किसी भी विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए एक प्रभावी एवं उत्तरदायी निगरानी व्यवस्था (Monitoring System) अत्यंत आवश्यक होती है। निगरानी के माध्यम से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा, संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन, सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण तथा कमियों एवं चुनौतियों की समय रहते पहचान की जा सकती है। यदि निगरानी प्रणाली सुदृढ़ हो तथा उसमें समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है। सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit), ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियाँ, मातृ समिति, जनसुनवाई, सामुदायिक निरीक्षण तथा डिजिटल निगरानी प्रणाली जैसे उपाय कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों की वास्तविक समस्याओं की पहचान होती है तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम शीघ्रता से उठाए जा सकते हैं।

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता और निगरानी व्यवस्था का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की उपलब्धता, पहुँच तथा गुणवत्ता अनेक भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से प्रभावित होती है। यदि स्थानीय समुदाय योजनाओं के प्रति जागरूक एवं सक्रिय हो तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था प्रभावी हो, तो मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की पहुँच, स्वीकार्यता तथा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, समुदाय की सक्रिय भागीदारी से लाभार्थियों में स्वामित्व की भावना विकसित होती है, जिससे योजनाओं की निरंतरता एवं स्थायित्व भी सुनिश्चित होता है।उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत शोध "मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता में सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था की भूमिका का अध्ययन" अत्यंत प्रासंगिक एवं समसामयिक है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि समुदाय की सहभागिता तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता, सेवा-प्रदाय की गुणवत्ता, लाभार्थियों की संतुष्टि, योजनाओं की पहुँच तथा स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करती है। साथ ही यह अध्ययन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यमान चुनौतियों की पहचान करते हुए ऐसी व्यवहारिक एवं नीतिगत अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा, जिनके आधार पर मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी, सहभागी, पारदर्शी तथा परिणामोन्मुख बनाया जा सके। इस प्रकार यह शोध न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग, स्थानीय निकायों तथा समुदाय आधारित संगठनों के लिए भी उपयोगी एवं मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व: मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता किसी भी राष्ट्र के समग्र सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित मातृत्व तथा समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान तथा अन्य अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की वास्तविक सफलता केवल सरकारी संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समुदाय की सक्रिय सहभागिता तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था पर भी समान रूप से आधारित होती है। यदि स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक संस्थाएँ कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचता है। इसके विपरीत सामुदायिक सहभागिता के अभाव तथा कमजोर निगरानी व्यवस्था के कारण अनेक योजनाओं का अपेक्षित लाभ पात्र महिलाओं एवं बच्चों तक नहीं पहुँच पाता, जिससे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है कि यह सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करेगा कि इन दोनों कारकों का मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता पर कितना प्रभाव पड़ता है। यह अध्ययन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, जन-जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा समुदाय आधारित निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायक होगा। साथ ही यह शोध नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा स्वयंसेवी संगठनों को कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार एवं नवाचार के लिए तथ्यपरक सुझाव प्रदान करेगा। इसके निष्कर्ष समुदाय आधारित भागीदारी को सुदृढ़ करने, सेवा वितरण की गुणवत्ता बढ़ाने, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, कुपोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी लाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रकार यह अध्ययन न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तथा समावेशी सामाजिक विकास को सशक्त बनाने की दिशा में भी अत्यंत सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।

सम्बंधित साहित्य: सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है।

नागपाल (2020) [4] ने भारतीय राज्यों के बीच बाल विकास में व्यापक अंतर देखा, विशेष रूप से शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में और यह भी पाया कि राज्य स्तरीय आर्थिक असमानताएँ बुनियादी सेवाओं तक पहुँच को निर्धारित करती हैं। ये सभी अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि शैक्षणिक पहुँच और सफलता केवल

व्यक्तिगत या पारिवारिक कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय और संरचनात्मक असमानताओं से भी प्रभावित होती है। इन खाइयों को पाटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना में समन्वित निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन जिलों में जो विकास में पिछड़े हैं, ताकि सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राजपा, एस० (2020) ने भारत में विभिन्न आयामों, जिनमें मातृत्व और शिशु देखभाल की निरंतरता भी शामिल है, के माध्यम से आईसीडीएस सेवाओं के उपयोग में सामाजिक-आर्थिक पैटर्न का विश्लेषण किया है। निष्कर्ष शहरी मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों में सेवा उपयोग को बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता को दर्शाते हैं। इसके लिए खाद्य पूरकों से परे सेवाओं में सुधार की आवश्यकता हो सकती है, जिनमें स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल (प्रीस्कूल) शामिल हैं। मीना (2017) के अनुसार, आईसीडीएस सेवाओं का औसत कवरेज 58.3% था। पूरक पोषण (एसएन) का कवरेज अधिकतम था, जबकि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचई) का कवरेज सीमित था। एसएन, टीकाकरण, प्रीस्कूल शिक्षा (पीएसई) और 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास निगरानी नियमित रूप से आयोजित की गई। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थीं।

पाण्डेय,ए० (2020): ने समन्वित बाल विकास परियोजना का गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा नवजात शिशु पर प्रभाव का अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया। शोध के उद्देश्य-

1. समन्वित बाल विकास परियोजना द्वारा गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा नवजात शिशुओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं एवं इन सेवाओं का गर्भवती एवं धात्री माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन।
2. समन्वित बाल विकास परियोजना द्वारा धात्री माताओं को दुग्धपान के के संबंध में दी जाने वाली जानकारी के फलस्वरूप नवजात शिशुओं पर प्रभाव का अध्ययन।

निष्कर्ष: समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना अपनी विभिन्न सेवाओ के माध्यम से न्यूनाधिक रूप से ग्रामीण परिवारों में गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में परिवर्तन लाने में सफल रही है तथा इसका सापेक्ष्य प्रभाव भी गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा नवजात शिशुओं में परिलक्षित होता है। लेकिन परियोजना अपने निहित लक्ष्यों के सन्दर्भ में अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला पाया है। परियोजना द्वाराग्रामीण परिवारों में गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा नवजात शिशुओं पर प्रभाव न ला पाने लिए जहां एक तरफ स्वयं परियोजना सेवाओं में व्याप्त अनियमितता, सेवाओं एवंकर्मचारियों में समन्वय का अभाव, कार्यकर्ताओं में समुचित प्रशिक्षण का अभाव, पयैवेक्षण का अभाव, संसाधनों का अभाव तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का केन्द्र से संबंधित गांव से दूर रहना आदि करके हैं वही दूसरी तरफ गामीणों मे व्याप्त अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता एवं परम्परावादिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का समुदायय से अच्छा संबंध न होना, आर्थिक स्थिति, उनमें जागरूकता को अभाव, अस्थायी निवास प्रवृत्ति आदि कारक भी अवरोध उत्पन्न करते हैं।

शोध विधि: इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि (Survey Method) का उपयोग किया गया। सर्वेक्षण के माध्यम से चयनित ग्रामीण महिलाओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर तथा साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करके आवश्यक तथ्यों का संकलन किया गया तथा प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए।

जनसंख्या: इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज व परसपुर विकास खण्डों की ग्रामीण महिलाओं को जनसंख्या के रूप में शामिल किया गया है।

न्यादर्श: इस अध्ययन में गोंडा जिले के करनैलगंज व परसपुर विकास खण्डों के 5-5 गावों में निवास करने वाली 400 ग्रामीण महिलाओं को न्यादर्श के रूप में शामिल किया गया है । इस नमूने का चयन गैर-संभाव्यता उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण पद्धति के आधार पर किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य- प्रस्तुत शोध का निम्नवत उद्देश्य है-

सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था का मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना: प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित परिकल्पना के अंतर्गत सम्पादित किया गया है-

सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था का मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

विश्लेषण-

उद्देश्य-सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था का मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना-सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था का मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका 1: सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था तथा कार्यक्रमों की सफलता के मध्य संबंध

सामुदायिक सहभागिता	कार्यक्रम सफल	सफल नहीं	कुल
अधिक	160	30	190
मध्यम	80	40	120
कम	20	70	90
योग	260	140	400

χ^2=74.58, df=2 तथा p-value=0.000

विश्लेषण-अधिक सामुदायिक सहभागिता एवं प्रभावी निगरानी वाले क्षेत्रों में कार्यक्रमों की सफलता अधिक पाई गई। $\chi^2 = 74.58$ तथा $p < 0.05$ होने के कारण शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।निष्कर्षतः सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था का कार्यक्रमों की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया।

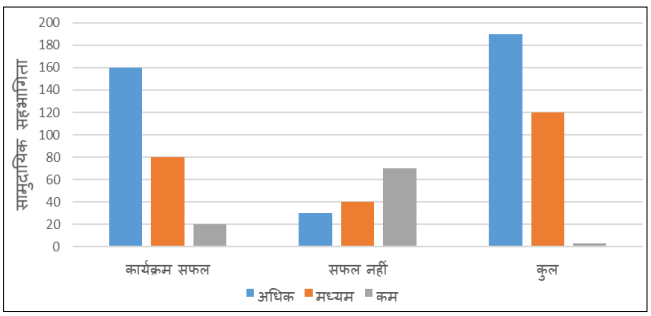

आकृति 1: ग्राफ-सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था तथा कार्यक्रमों की सफलता के मध्य संबंध

निष्कर्ष- इस शोध सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था का मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण किया गया। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में समुदाय की सहभागिता अधिक तथा निगरानी व्यवस्था प्रभावी थी, वहाँ कार्यक्रमों की

सफलता का स्तर सर्वाधिक पाया गया। अध्ययन के अनुसार अधिक सामुदायिक सहभागिता वाले 190 उत्तरदाताओं में से 160 (84.21%) ने कार्यक्रमों को सफल माना, जबकि केवल 30 (15.79%) ने उन्हें सफल नहीं माना। इसके विपरीत, मध्यम सामुदायिक सहभागिता वाले क्षेत्रों में 120 उत्तरदाताओं में से 80 (66.67%) ने कार्यक्रमों को सफल तथा 40 (33.33%) ने असफल बताया। वहीं, कम सामुदायिक सहभागिता वाले क्षेत्रों में स्थिति इसके विपरीत रही, जहाँ 90 उत्तरदाताओं में से केवल 20 (22.22%) ने कार्यक्रमों को सफल माना, जबकि 70 (77.78%) उत्तरदाताओं ने कार्यक्रमों को सफल नहीं माना। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जैसे-जैसे सामुदायिक सहभागिता एवं स्थानीय स्तर पर निगरानी की प्रभावशीलता बढ़ती है, वैसे-वैसे कार्यक्रमों की सफलता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

सांख्यिकीय परीक्षण के परिणामों से प्राप्त $\chi^2 = 74.58$, df = 2 तथा p-value = 0.000 यह प्रमाणित करते हैं कि सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था तथा कार्यक्रमों की सफलता के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संबंध विद्यमान है। चूँकि p-value 0.05 से कम है, इसलिए शून्य परिकल्पना "सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था का मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है" अस्वीकृत की जाती है तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी, स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा नियमित निगरानी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

वर्तमान निष्कर्ष पूर्ववर्ती अध्ययनों से भी सामंजस्य रखते हैं। World Health Organization (2022) के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता तब अधिक होती है जब स्थानीय समुदाय योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। इसी प्रकार UNICEF (2023) ने अपने विभिन्न अध्ययनों में उल्लेख किया है कि समुदाय-आधारित निगरानी, सामाजिक सहभागिता तथा स्थानीय संस्थाओं का सहयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पहुँच, गुणवत्ता तथा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार करता है। इसके अतिरिक्त Ministry of Women and Child Development द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) से संबंधित दिशा-निर्देशों में भी ग्राम स्तर पर समुदाय, पंचायत एवं मातृ समितियों की सक्रिय भागीदारी को कार्यक्रमों की सफलता का प्रमुख आधार माना गया है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता केवल सरकारी संसाधनों एवं प्रशासनिक प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समुदाय की सक्रिय सहभागिता, पारदर्शी निगरानी व्यवस्था, स्थानीय उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सहयोग भी इसकी सफलता के प्रमुख निर्धारक हैं। इसलिए कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए सामुदायिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ नियमित सामाजिक अंकेक्षण एवं निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है।

शोध की उपयोगिता- प्रस्तुत शोध "मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों की सफलता में सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी व्यवस्था की भूमिका का अध्ययन" अनेक दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी एवं प्रासंगिक है। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रम, जैसे समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), जननी सुरक्षा योजना (JSY), पोषण अभियान तथा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास में सुधार करना है। इन कार्यक्रमों की वास्तविक सफलता केवल योजनाओं के निर्माण एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी, जन-जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था पर भी आधारित होती है। यह अध्ययन इन सभी पक्षों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सामुदायिक सहभागिता और निगरानी व्यवस्था कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को किस सीमा तक प्रभावित करती है।

यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा कार्यक्रम संचालकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें यह जानकारी प्राप्त होगी कि किन क्षेत्रों में समुदाय की भागीदारी अधिक प्रभावी है तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु नई रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं। साथ ही, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन एवं सुधार करने में भी यह अध्ययन सहायक होगा।

यह शोध आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों (VHSNC), स्वयं सहायता समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा अन्य सामुदायिक संगठनों के लिए भी उपयोगी होगा। अध्ययन से यह ज्ञात होगा कि समुदाय के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता कार्यक्रमों के संचालन, लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुँच, नियमित स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, पोषण परामर्श तथा मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करती है। इससे इन कार्यकर्ताओं की भूमिका को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता-विकास कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सकेगी।यह अध्ययन लाभार्थी महिलाओं एवं परिवारों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इसके माध्यम से यह समझ विकसित होगी कि समुदाय की सक्रिय भागीदारी से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पोषण संबंधी जागरूकता, समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण तथा पोषण आहार की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार संभव है। इससे समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक व्यवहार, जागरूकता तथा सहभागिता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँच सकेगा।

शोध की उपयोगिता शैक्षिक एवं अनुसंधान क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन मातृत्व एवं बाल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, महिला अध्ययन तथा लोक प्रशासन जैसे विषयों में भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए एक उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य करेगा। इसके निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न राज्यों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में तुलनात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं। साथ ही, यह अध्ययन सामुदायिक सहभागिता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में नवीन शोधों के लिए आधार प्रदान करेगा।यह अध्ययन सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से समुदाय में सहयोग, सहभागिता, उत्तरदायित्व एवं सामूहिक निगरानी की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जब समुदाय स्वयं कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन में सक्रिय भूमिका निभाता है, तब योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ती है, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं में कमी आती है तथा लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्राप्त होती हैं। इससे महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, जीवन-गुणवत्ता तथा मानव संसाधन विकास में सकारात्मक परिवर्तन संभव होगा।

अंततः यह अध्ययन सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals–SDGs), विशेषकर लक्ष्य 2 (भुखमरी की समाप्ति एवं बेहतर पोषण), लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण) तथा लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण) की प्राप्ति में भी उपयोगी सिद्ध होगा। अध्ययन के निष्कर्ष मातृत्व एवं बाल विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी, समावेशी, पारदर्शी एवं

समुदाय-केंद्रित बनाने में सहायक होंगे तथा सरकार, स्थानीय प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों एवं समुदाय के मध्य समन्वय स्थापित कर माताओं एवं बच्चों के समग्र स्वास्थ्य, पोषण और विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सन्दर्भ

1. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): परिचालन दिशानिर्देश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2017.
2. World Health Organization: WHO recommendations on maternal health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2018.
3. भारत सरकार: पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan): संचालन दिशा-निर्देश,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2018.
4. नागपाल पी. भारत में बाल विकास की स्थिति। जर्नल ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट. 2020;23:24-43.
5. Rajpa S, Utilization of Integrated Child Development Services in India: Programmatic Insights from National Family Health Survey, 2016, Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17:31-97.
6. National Institute of Public Cooperation and Child Development: Training manual for Anganwadi workers on maternal and child health. New Delhi, India: NIPCCD, 2020.
7. पाण्डेय,अविनाश: समन्वित बाल विकास परियोजना का गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा नवजात शिशु पर प्रभाव का अध्ययन,शोध प्रबंध (समाज कार्य),महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 2020. http://hdl.handle.net/10603/288019
8. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0: दिशा-निर्देश,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2021.
9. United Nations Children's Fund: The state of the world's children 2021: On my mind-Promoting, protecting and caring for children's mental health. New York, NY: UNICEF, 2021.
10. International Institute for Population Sciences (IIPS), & ICF: National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: India. Mumbai, India: IIPS.
11. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: परिचालन दिशा-निर्देश,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2021.
12. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): कार्यान्वयन रूपरेखा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।, 2022.
13. World Health Organization: World health statistics 2022: Monitoring health for the SDGs. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2022.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.